



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1)

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 105]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

प्रकरण सं. OI/26/2017

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेरामिक रोलर्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोध जांच।

संख्या 14/52/2016 –डीजीएडी.—1. मै. फ्यूचूरा सेरामिक्स (प्रा.) लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग/आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन/याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक रोलर्स या रोलर्स (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के कथित पाटित आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत का उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका मै. फ्यूचूरा सेरामिक्स (प्रा.) लि. द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में दायर की गई है।

4. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनी के उत्पादन का घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है क्योंकि उसके पास भारत में रोलर्स के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा (70 प्रतिशत से अधिक) है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदक योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "सेरामिक रोलर्स" या "रोलर्स" हैं (जिन्हें बाजार शब्दावली में सेरामिक पाइप या ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है) और उनका प्रयोग भट्टी के एक छोर से दूसरे छोर तक टाइलों का परिवहन करने के लिए रोलर हर्थ किलन में किया जाता है। अपने चारों ओर घूमकर रोलर टाइलों का एक छोर से दूसरे छोर तक परिवहन करते हैं। सेरामिक रोलर का प्रयोग स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने के लिए एस.एस. (स्टेनलैस स्टील) की चादरों/पट्टे बनाने वाले उद्योगों में भी किया जाता है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

6. सेरामिक रोलर के प्रमुख प्रयोग भट्टी के एक छोर से दूसरे छोर तक टाइलों का परिवहन करने के लिए रोलर हर्थ किलन में किया जाता है। अपने चारों ओर घूमकर रोलर टाइलों का एक छोर से दूसरे छोर तक परिवहन करते हैं।

7. सेरामिक रोलरों की तकनीकी जरूरतों में इन वर्षों के दौरान निम्नलिखित के कारण बदलाव हो रहा है :

क. उच्चतर फायरिंग तापमान

ख. अपेक्षाकृत अधिक भार की टाइलों की फायर किया जाना

ग. टाइलों की बढी हुई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई

घ. किलन की ही अधिक लंबाई

ङ. फायरिंग साइकिल का अपेक्षाकृत तेज समय

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदक ने बताया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

घ. शामिल देश

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. (जिसे संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान उत्पादन लागत के आधार पर संबद्ध देशों में कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करके लगाया गया है।

च. निर्यात कीमत

11. निर्यात कीमत को एक द्वितीयक स्रोत डीजीसीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से भारित औसत आयात कीमत के रूप में निर्धारित किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजन किए गए हैं।

छ. पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, मालसूची में गिरावट के अनुसार भारी प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के फलस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. से आयातों में अचानक उछाल आया है। अतः याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि आयातों में भारी वृद्धि, आयात कीमत में गिरावट, भारी आधिक्य क्षमता और संबद्ध देश में उत्पादकों का अत्यधिक निर्यातमुखी होना संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के खतरे का दावा करने का आधार है।

झ. जांच अवधि

15. याचिकाकर्ता ने जाँच अवधि के रूप में 2015 से सितंबर 2016 (18 महीने) की अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 और जांच की अवधि (पीओआई) के आकड़ों का प्रस्ताव किया गया है। तथापि अधिक अद्यतन आकड़ों पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए, 1 अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 (12 महीनों) तक पीओआई तय करने का प्रस्ताव किया जाता है। क्षति जाँच अवधि के अप्रैल 13 – मार्च, 14, अप्रैल 14 – मार्च, 15, अप्रैल 15 – मार्च, 16 और जाँच अवधि की अवधि को शामिल करने पर विचार और प्रस्ताव किया गया है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

ट. समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

ठ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

इ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2017

Case No. OI- 26/2017

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Ceramic Rollers', originating in or exported from China PR

No.14/47/2016-DGAD.—1. M/s Futura Ceramics (P) Ltd (hereinafter referred to as the applicant/ domestic industry/petitioner) has filed an application/petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Ceramic Rollers or Rollers (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

A. Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s Futura Ceramics (P) Ltd as the domestic industry.
4. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes “a major proportion” of the domestic production since it is having a significant share in the production of Rollers in India (more than 70%). The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra

B. Product under Consideration

5. The product under consideration in the present petition is “Ceramic Rollers” or “Rollers” (also known as Ceramic pipes or tubes in market parlance) and is used in Roller Hearth Kilns to transport tiles from one end of the kiln to the other end. By rotating around themselves the rollers allow the tiles to be transported from one end to the other. The Ceramic Rollers are also used in Industries that make S.S. (Stainless Steel) Strips / Patta to manufacture Stainless Steel Utensils. It is classified under Chapter 69 of the Customs Tariff Act.
6. The main uses of Ceramic Rollers are used in Roller Hearth Kilns to transport tiles from one end of the kiln to the other end. By rotating around themselves the rollers allow the tiles to be transported from one end to the other.
7. The technical needs of Ceramic Roller is changing over the years due to:
 - a. Higher firing temperatures
 - b. Heavier tiles being fired
 - c. Increased Length, Breadth and Thickness of tiles
 - d. Longer length of the kiln itself
 - e. Faster time of firing cycle

C. Like Article

8. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country/territory

D. Country involved

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the “subject country”).

E. Normal Value

10. The petitioners have submitted that in the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries the Normal values in the subject countries have been estimated on the basis of cost of production; taking into account prevailing international prices of raw materials and cost of utilities in subject countries, conversion costs of the domestic industry, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

F. Export Price

11. The export price has been determined as the weighted average import price from subject country based on the transaction-wise import data obtained from a secondary source, DGCIS. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Marine insurance, Commission, Inland Freight, Port expenses and Bank charges to arrive at the net export price.

G. Dumping Margin

12. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de Minimis.

H. Injury and Causal Link

13. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.
14. The applicant has claimed that imports have spurted from China PR. Petitioner has therefore claimed that the imports are threatening material injury to the domestic industry. Applicant has submitted that there is significant increase in imports, decline in import price, significant surplus capacity and high export orientation of the producers in subject country as grounds for claiming threat of material injury to the domestic industry from subject imports.

I. Period of Investigation

15. Petitioner has proposed the period from 2015 to September 2016 (18 months) as the period of investigation. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI had been proposed. However, to make the required analysis on more updated data, the Authority has proposed to fix the POI from 1st April, 2016 to 31st March 2017 (12 months). The injury investigation period has been considered and proposed to cover the periods Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15, Apr'15-Mar'16 and the period of investigation.

J. Submission of information

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

K. Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

L. Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

M. Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority